

ग्रसाधारण

## **EXTRAORDINARY**

भाग II--**तप्य** 3--उपलक्ष (ii)

## PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

## PUBLISHED BY AUTHORITY

सं**० 464**]

नई विस्ली, मंगलवार, प्रवट्वर 24, 1972/कार्तिक 2, 1894

No. 464]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 24, 1972/KARTIKA 2, 1894

इस भाग में भिन्न पुरुठ संस्था वी जाती है जिससे कि यह बालग संकलन के रूप में रक्ता जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

#### MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

(Department of Industrial Development)

#### ORDER

New Delhi, the 24th October 1972

8.0. 679(E)/18A/IDRA/72.—Whereas the Central Government is of the opinion that Apollo Mills Ltd., Bombay, an industrial undertaking in respect of which an investigation has been made under Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), is being managed in a manner highly detrimental to public interest.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 18A of the said Act, the Central Government hereby authorises the Maharashtra State Textile Corporation, (hereinafter referred to as Authorised Controller) to take over the management of the whole of the said undertaking, namely, Apollo Mills Ltd., Bombay, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) The Authorised Controller shall comply with all directions issued from time to time by the Central Government.
- (ii) The Authorised Controller shall hold office for five years from the date of publication in the Official Gazette of this notified Order.
- (iii) The Central Government may terminate the appointment of the Authorised Controller earlier, if it considers it necessary to do so.
- 2. This Order shall have effect for a period of five years commencing from the date of its publication in the Official Gazette.

[No. F. 3/43/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

# श्रीद्योगिक विकास मंत्रालय (ओद्योगिक विकास विभाग)

ग्रादेश

नई दिल्ती, 24 ग्रक्तूबर, 1972

का० ा० 679(म)/18ए/म्राई० डी० म्राए० ए०/72.— यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि म्रापोलो मित्स लिमिटेड, बम्बई, म्रीद्योगिक उपक्रम का जिसकी बाबत उद्योग (विकास म्रीर विमिनयमन) म्रिधिनयम, 1951(1951 का 65) की धारा 15 के म्रधीन म्रन्वेणन किया जा चुका है, प्रबन्ध इस रीति से किया जा रहा है कि लोक हित में म्रित महितकर है:

श्रतः श्रव, उक्त अधिनियम की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, महाराष्ट्रराज्य वस्त्र निगम लि०, को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत नियंत्रक कहा गया है) उक्त उपक्रम, श्रयात् अपोलो मिल्म लिमिटेड, बम्बई, का पूर्ण प्रबन्ध निम्नलिखित निबन्धनों श्रीर शर्ती के अधीन रहते हुए, ग्रहण करने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत करती है, ग्रर्थात् :--

- (1) प्राधिकृत नियंवणक केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निकाले गए सभी निदेशों का पालन करेगा ।
- (2) प्राधिकृत नियंत्रक राजपन्न में इस्त ग्रादेश के प्रकाशन की तारीख से 5 वर्ष के लिए पदामीन रहेगा।
- (3) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति यदि वह ऐसा करना ध्रावश्यक समझे तो , पहले ही समाप्त कर सकेगी ।

यह प्रादेश शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की वारोज से पांचवर्ष की श्रवधि के लिए प्रभावी होगा।

[मं र एक ० 3/43/72-सी व्यू वसी ०] के र एस ० भटनागर, संयुक्त सचिव ।